ग्लॉस्टरशर, इंगलैण्ड, के कॉट्सवोल्ड जिले के गांव चिपिंग कैम्पडन के लोग 17 वीं सदी से "ओलम्पिक" आयोजित कर रहे हैं। आम ओलम्पिक के विपरीत कॉट्सवोल्ड ओलम्पिक में कुछ गैर पारम्परिक खेल होते थे, जैसे, स्लैजहैमर थ्रोइंग, वीलबरो रेसिंग, मॉरिस डान्सिंग और शिन (पिंडली) किकिंग। इस ओलम्पिक की शुरुआत एक वकील रॉबर्ट डोवर ने की थी। उसका मत था कि, खेल समाज में सद्भावना बढ़ाते और गरीब-अमीर की खाई मिटाते हैं, साथ-साथ इससे कसरत भी होती है, जो कि राज्य की सुरक्षा के लिए जरुरी है। इसलिए इंगलैण्ड के किंग जेम्स ने उसकी बात मान ली और 1612 में इन खेलों का पहला आयोजन हुआ। पहले खेल एक प्राकृतिक एम्फिथिएटर में हुए जिसे अब डोवर्स हिल कहते हैं, पर तब इसका नाम किंगकोम्ब मैदान था। हर साल लकड़ी का एक दुर्ग (डोवर कासल) बनाया जाता था। समाज के हर वर्ग के लोग इन खेलों में शामिल होते थे। पर प्यूरीटान्स (परिशुद्धतावादी) इससे नाराज थे। उनका मानना था कि, ये खेल शराब व अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं। असल में इन लोगों को चर्च अवकाश के दिन किसी भी उत्सव का आयोजन पसंद नहीं था। बाद में सन् 1643 में खेलों का आयोजन बंद हो गया। वर्ष 1666 में राजतंत्र के पुनः बहाल होने के बाद खेल दोबारा शुरु हुए पर तब तक डोवर की मौत हो चुकी थी और उसके मार्ग दर्शन के अभाव में खेलों में धीरे-धीरे शराब का प्रचलन बहुत बढ़ गया, साथ ही नग्नता व अनैतिकता भी बढ़ गई। बाद में आयोजकों को कई तरह की समस्याएं होने लगीं, क्योंकि 1820 के दशक में खेलों में काम आने वाली काफी ज़मीन लोगों ने खरीद ली थी जिसका किराया देना पड़ता था। सन् 1852 में आखिरी बार इन खेलों का आयोजन हुआ फिर ये बंद हो गए। सौ साल बाद 1951 में फैस्टिवल ऑफ ब्रिटेन के रुप में इन खेलों का पुनः आयोजन हुआ और तब ये इतने लोकप्रिय हुए कि, हर वर्ष खेल आयोजित करने का फैसला हुआ। लेकिन क्षेत्र में फुट एण्ड माउथ डिज़ीज़ फैलने से ऐसा नहीं हो पाया। फिर, सन् 1965 में रॉबर्ट डोवर्स गेम्स सोसायटी की स्थापना हुई और खेल आयोजन चालू हुआ, तब से ये खेल हर साल होते हैं और हजारों लोग इनमें भाग लेने आते हैं।

मु.मंत्री शिंदे अपनी पार्टी शिवसेना को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल करवायेंगे

मु.मंत्री शिंदे चाहते हैं कि, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में स्थान मिलने का फायदा पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर मिले

मुंबई, 21 फरवरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अब शिवसेना से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने के प्रयास में लगने वाले हैं। अगले साल होने वाले महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनावों से पहले पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा हो रही है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिवसेना को मिलने वाली जगह से न सिर्फ महाराष्ट्र के सियासी समीकरण साधे जाएंगे। बल्कि उद्धव ठाकरे को कमजोर करने में यह दांव भी शिंदे गुट को मुफीद लग रहा है। दरअसल यह सारी कवायद पार्टी के भीतर तब और ज्यादा जोर मारने लगी, जबसे शिंदे गुट को आधिकारिक रूप से शिवसेना का तमगा और चुनाव चिन्ह मिल गया है। यही वजह है कि अब शिंदे गुट पूरी तरीके से पार्टी से न सिर्फ उद्धव ठाकरे युग को खत्म करने की कवायद में लग गया है। बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की सभी जोर आजमाइश भी शुरू कर दी गई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगले साल महाराष्ट्र में चुनाव हैं। ऐसी दशा में अगर शिंदे गुट की पहचान को महाराष्ट्र में स्थापित करके अगले साल फिर से सत्ता में वापसी करनी है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिवसेना को जल्द से जल्द जगह भी देनी होगी। इसको लेकर पार्टी के भीतर न सिर्फ लगातार बातचीत हो रही है, बल्कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक से पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने विस्तार से चर्चा की है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पिछले सप्ताह महाराष्ट्र पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह के संज्ञान में भी यह बात लाई गई है। महाराष्ट्र की सियासत को समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अब एकनाथ शिंदे के ऊपर शिवसेना पार्टी का तमगा और पार्टी का सिंबल मिलने के बाद दबाव तो पड़ ही रहा होगा।

हालांकि शिवसेना से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर कोई अटकलें और रोड़े नहीं हैं। वह कहते हैं कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो शिवसेना को उसमें हिस्सेदारी भी मिलेगी। इसके पीछे तर्क देते हुए महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक हिमांशु शितोले कहते हैं कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है शिवसेना के ऊपर दबाव तो पड़ ही रहा है। वह बताते हैं कि यह दबाव सिर्फ इस बात का नहीं है कि चुनाव आयोग की ओर से शिंदे गुट को मिली शिवसेना की मान्यता और चुनाव चिन्ह के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले। दबाव इस बात का है कि असली चुनावी परीक्षा 2024 के विधानसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे गुट को मिली शिवसेना की बागडोर के बाद सीधा मुकाबला उद्धव ठाकरे की पार्टी से होने वाला है। यही वजह है कि सिर्फ शिवसेना ही नहीं बल्कि भाजपा भी महाराष्ट्र के सभी सियासी समीकरणों को हर नजरिए से देख कर एक-एक कदम फूंक कर आगे रख रही है।

महाराष्ट्र में हुए बड़े सियासी उलटफेर के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिंदे ने शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, उससे कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अभी भी कई नेता ऐसे हैं, जिनकी आस्था उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे के परिवार के प्रति बनी हुई है। विश्लेषकों का अनुमान है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में उद्धव ठाकरे के परिवार से संबंध रखने वाले किसी नए नेता की फिलहाल न तो एंट्री होगी और न ही उसे बरकरार रखा जा सकेगा। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना की बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के विधायक सांसद और तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। फिलहाल अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि शिवसेना की नई कार्यकारिणी में व्यापक फेरबदल किए जा सकते हैं। हालांकि यह फेरबदल किस तरीके के होंगे यह तो कार्यकारिणी की बैठक के बाद ही पता चलेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र में जितना सजग होकर एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी से जुड़े नेता चल रहे हैं, उससे ज्यादा भाजपा एक-एक कदम सोच समझ कर रख रही है। राजनीतिक विश्लेषक एस.एन. धर कहते हैं कि दरअसल अगले साल होने वाले दो महत्वपूर्ण चुनाव महाराष्ट्र के हाल के दिनों में हुए बड़े बड़े घटनाक्रम से आंके जाएंगे। इसमें अगले साल होने वाले लोकसभा का चुनाव भी शामिल है और महाराष्ट्र में अगले साल होने वाले विधानसभा का भी चुनाव शामिल है। धर कहते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है, उससे न सिर्फ सियासत के गलियारों में हलचल मची थी, बल्कि महाराष्ट्र की जनता भी एकबारगी सन्न रह गई थी।

वसुंधरा राजे जोधपुर पहुंचीं

जोधपुर, 21 फरवरी (कासं)। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार सुबह रोहट से जयपुर लौटते समय कुछ देर के लिए जोधपुर में रुकीं। एयरपोर्ट लॉज में उन्होंने भाजपा नेताओं से मुलाकात की।

आज भाजपा में वसुंधरा ग्रुप से जुड़े नेता एक बार फिर सक्रिय नजर आए। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, पूर्व सांसद जसवंतसिंह विश्नोई, जेडीए के पूर्व चेयरमैन महेंद्र राठौड़, पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी और पूर्व सांसद रामनारायण डूडी सहित अन्य नेता उनकी अगवानी करने एयरपोर्ट पहुंचे।

- जोधपुर में वसुंधरा समर्थक भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया।
- सूत्रों के अनुसार इस बार वसुंधरा 4 मार्च को अपना जन्मदिन सालासर में मनाएंगी।

वसुंधरा ने यहां काफी देर तक नेताओं से बात की और जोधपुर जिले का राजनीतिक फीडबैक भी लिया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जोधपुर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े थे।

पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण लाल पंचारिया, पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़, पूर्व विधायक जोगाराम पटेल, पूर्व मंत्री मेघराज लोहिया, पूर्व मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, पूर्व विधायक मदन राठौड़, कमसा मेघवाल, अर्जुनलाल गर्ग, भाजपा प्रदेश मंत्री के.के विश्नोई सहित अन्य नेता मौजूद रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बार अपना जन्मदिन 4 मार्च को मनाएंगी।

वैसे तारीख के हिसाब वसुंधरा राजे का जन्मदिन 8 मार्च को आता है और उस दिन महिला दिवस पर भी होता। लेकिन इस बार होली का त्यौहार होने के कारण वह 4 तारीख को सालासर में आयोजन कर अपना जन्मदिन मनाएंगीं। जोधपुर के नेताओं से इस बारे में भी चर्चा की गई।

लॉरेंस विश्नोई के करीबी लोगों पर एन.आई.ए. की रेड

एन.आई.ए. की टीम बालेसर और वीतराग सिटी में पहुंची

जोधपुर, 21 फरवरी (कासं)। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की तरफ से आज देश में कई कुख्यात अपराधियों के यहां पर एक साथ रेड डाली गई। कुख्यात अपराधी लॉरेंस विश्नोई से जुड़े उसके गुर्गों एवं संपर्क वालों के यहां पर सर्च चलाया गया। दोपहर तक पुलिस ने हालांकि, इसकी अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं की है। मगर पुलिस से इमदाद मांगी गई। ग्रामीण में बालेसर के भाटेलाई इस बारे में पुष्ट जानकारी नहीं दी।

वहीं सूत्रों के मुताबिक एन.आई.ए. ने कुख्यात अपराधी लारेंस विश्नोई और उसके जुड़े संपर्क वाले लोगों एवं गुर्गों पर सर्च किया है। लारेंस का पाकिस्तान से संपर्क होने की जानकारी सामने आने के बाद एनआईए सतर्क हो गई है। कुछ दिन पहले इस बारे में खुलासा हुआ था। पंजाबी सिंगर मूसेवाला हत्याकांड के बाद कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे है।

- हालांकि स्थानीय पुलिस ने अधिकृत रूप से रेड की पुष्टि नहीं की, परन्तु पता चला है कि एन.आई.ए. की टीम ने स्थानीय पुलिस से सहयोग मांगा है।
- सूत्रों के अनुसार लॉरैन्स विश्नोई का पाकिस्तान से सम्पर्क होने का खुलासा होने के बाद एन.आई.ए. का शिकंजा इस गिरोह पर कसता जा रहा है।

पुरोहितान में एक अपराधी घर के साथ यहां हिस्ट्रीशीटर पर गत दिनों हुई फायरिंग के केस में वीतराग सिटी में भी सर्च चला है। ज्यादा जानकारी इस बारे में पुलिस अधिकारी देने से कतराते रहे। एनआईए ने स्थानीय पुलिस से सहयोग मांगा है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि, एनआईए की रेड को लेकर उनसे इमदाद मांगी गई थी। पुलिस बल को बालेसर भेजा गया था। मगर उन्होंने किस बाबत कार्रवाई की लॉरैंस अपने गुर्गों से बड़ी रंगदारी वसूलने का काम करवा रहा था। जयपुर में बार क्लब में हुई फायरिंग के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लाई थी। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की अभिरक्षा में वह अभी चल रहा है। इस मामले में कई बड़े चौकानें वाले खुलासे एन.आई.ए. कर चुकी है। इसके तार जोधपुर में जुड़े होने की संभावना के मद्देनजर आज गुर्गों के कुछ ठिकानों पर सर्च चलाया गया है।

अनूपगढ़ में भी छापे

अनूपगढ़, (कासं)। एनआईए ने लॉरेंस, रोहित गोदारा, नीरज बवाना समेत कई गैंगस्टरों के ठिकानों पर छापेमारी की। सुबह 3 बजे से ही एनआईए ने अनूपगढ़ के गांव 65 जीबी, 61 जीबी और 62 जीबी में छापे मारे। इस दौरान दो लोगों को राउंडअप किया गया था, जिनसे एनआईए ने रामसिंहपुर पुलिस थाने में करीब 3 घंटे तक पूछताछ की।

मंगलवार सुबह 3 बजे एनआईए की टीम गांव 65 जीबी पहुंची और एक घर में छापेमारी की। यहां से एनआईए ने एक व्यक्ति को राउंडअप किया और उसे लेकर रामसिंहपुर पुलिस थाना पहुंची। बताया जा रहा है कि गांव 65 जीबी के जिस घर में एनआईए ने छापा मारा था। उस घर का एक सदस्य विदेश में रहता है। एनआईए की दूसरी टीम ने गांव 61 जीबी में पहुंचकर एक घर में छापामारी की और वहां से भी एक व्यक्ति को राउंडअप किया। दोनों व्यक्तियों से लगभग 3 घंटे तक रामसिंहपुर पुलिस थाना में पूछताछ की और उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। अनूपगढ़ के गांव 62 जीबी में भी एनआईए की टीम ने विदेश में रह रहे एक परिवार के घर पर छापा मारा।

- 61जीबी और 65 जीबी गांव के जिस घर में एन.आई.ए. ने छापा मारा, उस घर का एक सदस्य विदेश में रहता है।

मधुसूदन मिस्त्री से काम लेकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जोशी निर्वाचित ए.आई.सी.सी. सदस्य हैं, जबकि वो स्पीकर हैं। इस बात पर अभी बहस जारी है कि, स्पीकर एक स्वतंत्र हस्ती होता है अथवा एक स्पीकर के रूप में वो किसी राजनीतिक दल का हिस्सा होता है ? अन्य राज्यों में भी कई असमान्यताएं हैं। हमेशा सुखियों में रहने वाले कृष्णा अल्लूवेरा, जो पी.सी.सी. डैलिगेट तक नहीं हैं, को दिल्ली से डैलिगेट बनाया गया है, जबकि, वो आन्ध्र प्रदेश से हैं। राहुल गाँधी के एक पूर्व बॉडी गार्ड, जो अब उनके स्टाफ में है तथा राहुल के नजदीक माने जाते हैं, को दिल्ली से ए.आई. सी.सी. सदस्य बनाया गया है, वो केरल से हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते, विभाकर शास्त्री को ड्रॉप किया गया है और ए.आई.सी.सी. सदस्य नहीं बनाया गया है, जबकि, हाल ही में सम्पन्न राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो राजस्थान के मीडिया चेयरमैन थे।

प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं कि, इतने सारे डैलिगेट्स को क्यों हटाया गया है। तथा सभी उत्तर के.सी.वेणुगोपाल की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो सभी निर्णय ले रहे हैं, सूचियों में कांट-छांट कर रहे हैं; कुछ अनुपयुक्त लोगों को लिस्ट में शामिल कर रहे हैं और अनेक योग्य लोगों को छोड़ रहे हैं। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाली कांग्रेस इलैक्शन अथॉरिटी ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का संचालन किया था, दिन रात एक कर के पी.सी.सी. अध्यक्ष बनाए थे, लेकिन, वेणुगोपाल ने सूचियाँ अपने हाथ में ले लीं, मिस्त्री को उपेक्षित कर के। दुःखी मिस्त्री ने सारा काम वेणुगोपाल पर छोड़ दिया। वेणुगोपाल ने पी.सी.सी.अध्यक्षों से सीधे ही सूचियाँ मंगवाई और उनमें काट-छांट की। सूत्रों का कहना है कि लिस्ट बनाने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की न्यूनतम या नहीं के बराबर भूमिका है। उन्हें तो जो भी भेजा जा रहा है इस पर वे हस्ताक्षर कर रहे हैं। क्या खड़गे जी ने उस लिस्ट पर साइन किए जिसमें ए.आई.सी.सी. सदस्य के रूप में उनका नाम था? और क्या ऐसा ही वेणुगोपाल के साथ था? यही वजह है कि इलैक्शन अथॉरिटी गठित की गई थी और अभी तक इसने अच्छा काम किया था और इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली थी। इस कदम का लक्ष्य है राहुल की नई कांग्रेस।

- कृष्णा अल्लुवेरा, जो भी पी.सी.सी. सदस्य नहीं हैं, उन्हें दिल्ली से ए.आई.सी.सी. का सदस्य बनाया गया है, हालांकि वे आंध्र के हैं। इसी प्रकार राहुल गांधी के "बॉडीगार्ड" जो अब उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं और केरल के रहने वाले हैं, को भी दिल्ली से ए.आई.सी.सी. का सदस्य बनाया है।
- पूर्व प्र.मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र विभाकर शास्त्री, जो भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान के मीडिया चेयरमैन बनाये गये थे तथा राहुल गांधी के नजदीक के लोग हैं, ए.आई.सी.सी. सदस्य नहीं बनाये गये।
- यह भी कहा जा रहा है कि, मल्लिकार्जुन खड़गे का लिस्ट से कोई लेन-देन नहीं, उन्होंने तो वहीं हस्ताक्षर किये, जहां उन्हें कहा गया।

'बाड़मेर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। वे मंगलवार को एच.पी. सी.एल. राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड कॉम्प्लेक्स में प्रैस से बात कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि इस प्रोजैक्ट की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी के स्वप्नों- आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया- के अनुरूप की गई है। राजस्थान के बाड़मेर नगर में स्थित ग्रीन फील्ड रिफायनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एच.पी.सी .एल.) की जॉइन्ट वेन्चर कंपनी एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफायनरी लिमिटे (एच.आर.आर. एल.) तथा गवर्नमैन्ट ऑफ राजस्थान (जी.ओ.आर.) द्वारा स्थापित की जा रही है तथा इसमें इन दोनों की साझेदारी क्रमशः 74 प्रतिशत तथा 26 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट की परिकल्पना 2008 में की गई थी तथा इसका प्रारम्भिक अनुमोदन 2013 में हुआ था।

पुतिन ने राष्ट्रपति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि यूक्रेन को हथियारों के अलावा इंटैलीजेंस के साधन उपलब्ध करवाकर अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को हराने के जतन कर रहे हैं। पुतिन इस विवाद को और व्यापक करने की भी धमकी दे रहे हैं।

पुतिन के उपेक्षापूर्ण बयानों में निश्चित रूप से हताशा के स्वर हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगातार प्राप्त हो रहे अत्याधुनिक हथियारों और इंटैलीजैंस ने पुतिन के लिए यूक्रेन पर पार पाना एक तरह से असंभव कर दिया है। यह भी खबरें हैं कि रूस के राष्ट्रपति के लिए उनकी घरेलू स्थिति लगातार अस्थिर बनती जा रही है।

विशेषज्ञ ध्यान दिला रहे हैं कि पुतिन का आज का भाषण उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बतलाता है। वह कुछ वैकल्पिक बातें कर रहे हैं जो जमीनी स्थिति से अलग हैं। अपने प्रसारण में पुतिन ने आरोप लगाया कि युद्ध के लिए युक्रेन की सरकार दोषी है।

रूस इस युद्ध को लड़ने के लिए बाध्य है क्योंकि यूक्रेन की सरकार उसके विरूद्ध पश्चिमी देशों के एजेण्डे को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही पुतिन को यह समझ आ गया है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की दीर्घकालीन प्रतिबद्धताओं के कारण, उनके पास युद्ध जीतने का मौका ना के बराबर है।

पुतिन एक अन्य गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनका एक महत्वपूर्ण सहयोगी एवं भाड़े के सैनिकों वाला "वैगनर ग्रुप" रूस की सरकार और नौकरशाही को लेकर बेचैन है। चूंकि पुतिन की नियमित सेना किसी तरह की सफलता प्राप्त करने में विफल रही है, इसलिए वैगनर ग्रुप एक वैकल्पिक सत्ता केन्द्र के रूप में तेजी से उभर रहा है।

यह भी मुमकिन है कि एक संभावित घरेलू झड़प पुतिन के मुंह बांए खड़ी है और ये बाध्यताएं कहीं ना कहीं आगे का मार्ग दिखा रही हैं और रूस के राष्ट्रपति के लिए ये अनिवार्य बन गई हैं।

'हिन्दुस्तान में चुनाव वातावरण गर्माया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दूँ- मुझे नहीं मालूम कि चुनाव का सीजन भारत या दिल्ली में शुरु हुआ है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि यह लंदन, न्यूयॉर्क में शुरु हो गया है।"

पिछले 15 दिन से "हम अडानी के हैं कौन" शीर्षक वाली श्रृंखला के अन्तर्गत, रोजाना तीन सवाल पूछ रही कांग्रेस की बढ़ती स्वीकार्यता से परेशान, जयशंकर ने अपनी चहेती समाचार एजेंसी ए.एन.आई. को एक विस्तृत इन्टरव्यू दिया। ज्ञातव्य है कि 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद, पी.टी.आई. का स्थान ए.एन.आई. ने ले लिया है।

एक सोची-समझी कोशिश के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के कम्यूनिकेशन एवं मीडिया मैनेजमैंट प्लानर्स ने आज विदेश मंत्री की सेवायें लीं ताकि जनता का ध्यान अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे से हटाया जा सके, क्योंकि इस मुद्दे के चलते, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गौतम अडानी के विवादित व्यावसायिक ग्रुप के गहरे रिश्तों के उजागर होने का खतरा मँडरा रहा है।

और इसके बाद, जयशंकर बी.बी.सी. से कांग्रेस पर शिफ्ट हो गये, और राहुल गांधी पर हमला बोल दिया, जिन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि वे (राहुल) विदेश नीति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते तथा उन्हें "कुछ और जानने-सीखने की जरूरत है।" उन्होंने कांग्रेस नेता द्वारा अक्सर की जा रही उस आलोचना के लिये उन पर हमला बोला, जिसे वे सरकार की "रक्षात्मक" (डिफेंसिव) चीन नीति कहते हैं।

डॉ. जयशंकर ने कहा, "अगर मुझे इस चीन नीति का सार बताना पड़े, तो कृपया इस बात की ओर ध्यान मत दीजिये कि सरकार कहीं डिफेन्सिव रुख अपना रही है, ... हम कहीं दब्बूपन से काम ले रहे हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ कि अगर हम झुकने की नीति से काम ले रहे थे तथा एल.ए.सी. (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) पर भारतीय सेना किसने भेजनी थी। वे राहुल गांधी ने तो नहीं भेजी थी, वे नरेन्द्र मोदी ने ही भेजी थीं।"

उन्होंने कहा, "आज चीन सीमा पर हमारे इतिहास की (सेना की) सबसे बड़ी शांतिकालीन तैनाती है। हम वहाँ बहुत खर्च और प्रयास के साथ सेना तैनात किये हुये हैं। इहमने इस सरकार में सीमा पर इन्फ्रास्ट्रक्चर लागत पाँच गुना बढ़ा दी है। अब मुझे बताइये कि कौन है रक्षात्मक तथा समझौतावादी वास्तव में सच कौन बोल रहा है? चीजों को सही चित्रित कौन कर रहा है? इतिहास के साथ टेबल के नीचे पैर से छेड़छाड़ कौन कर रहा है?"

कांग्रेस के प्रति जयशंकर की पूर्वाग्रहयुक्त तथा गहरी पैठी हुई निजी नाराजगी उस समय खुलकर सामने आ गई, जब उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1980 में सत्ता में आने के शीघ्र बाद ही, उनके पिता डॉ. के सुब्रमण्यम को सैक्रेटरी, डिफ्रेंस प्रोडक्शन के पद से हटा दिया था तथा राजीव गांधी के शासनकाल में, उनको सुपरसीड करके, उनके एक जूनियर को कैबिनेट सैक्रेटरी बना दिया गया था।

उन्होंने कहा, "मैं एक उत्कृष्ट विदेश सेवा अधिकारी बनना चाहता था। और मेरी सोच में, कुछ उत्कृष्ट करने की परिभाषा यही थी कि विदेश सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुआ जाये। हमारे परिवार में, दबाव जैसा कुछ था, हालाँकि मैं इसे दबाव नहीं कहना चाहूँगा, किन्तु हम सब इस तथ्य से प्रति सचेत जरूर थे कि मेरे पिता, जो एक ब्यूरोक्रेट थे, सचिव बन तो गये थे, लेकिन उन्हें सचिव पद से हटा दिया गया था। वे उस समय, 1979 में, जनता सरकार में, संभवतः सबसे कम उम्र के सचिव थे।"

यह जानकारी देते हुये, कि 2011 में हुये उनके पिता के निधन के बाद, सरकार में सचिव बन गये थे, जयशंकर ने कहा कि वे विदेश सचिव 2015 में बने थे। जब उनसे एक ब्यूरोक्रेट से एक कैबिनेट मंत्री तक की यात्रा के बारे में पूछा गया तो जयशंकर ने कहा, "जैसा कि मैंने कहा कि मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। 2018 में, मैं अपनी सेवा यात्रा पूरी करके बड़ा प्रसन्न था, लेकिन मेरी यात्रा का अंत टाटा संस में हुआ। मैं वहाँ अपना अच्छे से अच्छा योगदान दे रहा था, मुझे वे लोग पसंद थे और मेरे ख्याल से, उन्हें भी मैं पसंद था। तभी पूरी तरह आकस्मिक रूप से, एक राजनैतिक अवसर मेरे सामने था। और यह राजनैतिक अवसर कुछ इस प्रकार का था कि मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत पड़ी क्योकि मैं उसके लिए तैयार नहीं था।...... इसलिये मैंने उस पर, थोड़ा ही सही, विचार जरूर किया।"

प्रधानमंत्री की ओर से आये उस फोन-कॉल की याद करते हुए, जिसमें उन्हें 2019 की नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था, जयशंकर ने कहा कि यह सब कुछ एक आश्चर्य के रूप में ही आया था। उन्होंने केन्द्रीय कैबिनेट में शामिल होने का जिक्र करते हुये कहा, "यह विचार ही मुझे कभी नहीं आया, और मेरे ख्याल से, मेरे मिलने-जुलने वालों के मन में ही यह बात कभी आई थी।"

जयशंकर ने कहा, "मैं मंत्रिमंडल में शामिल तो हो गया, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं स्वयं विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैंने जीवनभर राजनेता देखे थे। विदेश सेवा में आपको एक काम तो करना ही होता जो अन्य सेवाओं की अपेक्षा विदेश सेवा में कहीं ज्यादा करना होता है और वह काम यह है कि आप राजनेताओं को बड़े नजदीक से देखते हैं, क्योंकि आप उन्हें विदेश में भी देखते हैं। आपको उनके बहुत नजदीक रहकर काम करना होता है, उन्हें परामर्श देना होता है। इस प्रकार, राजनेताओं देखना एक चीज है किन्तु राजनीति में वास्तव में शामिल होना, कैबिनेट मंत्री बनना, राज्यसभा के लिये खड़ा होना, अलग प्रकार की चीज है। जब मुझे मंत्री पद के लिये चयनित किया गया, उस समय में संसद सदस्य भी नहीं था। इस प्रकार, ये सब चीजें एक-एक करके घटित हुईं। मैं राजनीति में उतर गया, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। आप दूसरों को देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं।"

संघ के पथ संचलन के खिलाफ तमिलनाडू सरकार सुप्रीम कोर्ट में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 फरवरी। तमिलनाडू सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश पर स्टे लगवाने को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट के आदेश में चेन्नई व तमिलनाडू के अन्य जिलों में आर.एस.एस. को पथ संचलन की अनुमति प्रदान की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि "इस प्रकार के जुलूस की अनुमति दिए जाने से कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएं खड़ी जो सकती हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने आर.एस.एस. को पथ संचलन की अनुमति प्रदान करते हुए कहा कि राज्य की जनता के संभाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकारों की जरूर रक्षा होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने आर.एस.एस. से कहा था कि वह पथ संचलन के रूट को लेकर तीन विभिन्न तिथियों पर ताजा आवेदन प्रस्तुत करे। कोर्ट ने तमिलनाडू पुलिस को निर्देश दिए थे कि वह राज्य के विभिन्न जिलों की सार्वजनिक सड़कों पर उक्त किसी भी तिथि पर पथ संचलन की अनुमति दे। आर.एस.एस. ने अनुरोध किया है कि उसे पूरे राज्य में एक म्यूजिकल बैन्ड के साथ अपनी वेशभूषा में पथ संचलन करने दिया जाए।

- तमिलनाडू सरकार ने हाई कोर्ट के, संघ को पथ संचलन की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और कहा है कि, पथ संचलन से व्यवस्था बिगड़ सकती है।

मिराज ग्रुप के 20 ठिकानों पर मुंबई आयकर टीम के छापे

उदयपुर, 21 फरवरी (कासं)। आयकर विभाग ने मंगलवार को मिराज ग्रुप पर रेड की। आयकर विभाग की मुबंई की टीमों ने मिराज ग्रुप के मुंबई, उदयपुर, नाथद्वारा सहित अन्य शहरों में 20 से अधिक ठिकानों पर एक साथ रेड की। कार्यवाही अभी भी जारी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पूरी कार्रवाई आयकर विभाग की मुंबई टीम के निर्देशन में चल रही है। मिराज ग्रुप की फूड, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट, फिल्म प्रोडक्शन, हॉस्पिटेलिटी, पाइप्स एंड फिटिंग, रिटेल, डिजिटल, इंजीनियरिंग सेक्टर्स से संबंधित बीस कंपनियां हैं। मिराज ग्रुप के फाउंडर मदन पालीवाल सहित मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ सहित अन्य पदाधिकारियों के घर और कार्यालयों से आयकर टीमें दस्तावेज जुटा रही हैं। आयकर विभाग की इस कार्रवाई में करोड़ों की टैक्स चोरी और अघोषित संपत्ति का खुलासा हो सकता है।

गौरतलब है कि गत वर्ष मिराज ग्रुप पर जीएसटी चोरी के मामले में भी कार्रवाई हुई थी। इस कार्रवाई में करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ था, तब मिराज के निदेशक को गिरफ्तार भी किया गया था।

संदेह है कि शैल कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी का रोटेशन होता है, ऐसे में अन्य एजेंसियां भी मिराज ग्रुप पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि चार महीने पहले अक्टूबर 2022 में ही मिराज गुप के फाउंडर मदन पालीवाल ने विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का भी लोकार्पण समारोह आयोजित किया था।

- मिराज ग्रुप के संस्थापक मदन पालीवाल नाथद्वारा में विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा बनवा कर चर्चा में आए थे।
- आयकर विभाग की मुंबई टीम ने मिराज ग्रुप के मुंबई सहित उदयपुर, नाथद्वारा व अन्य शहरों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की।
- गत वर्ष मिराज ग्रुप पर जी.एस.टी. चोरी के आरोप में कार्यवाही हुई थी तथा मिराज ग्रुप के प्रमुख मदन पालीवाल गिरफ्तार भी हुए थे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908